गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 142
दि. 21.09.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भर भारत से गुजरता है : पीएम

गांधीनगर, 20 सितंबर :प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को भावनगर में आयोजित 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया तथा विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं। उन्होंने शुक्रवार को हुए एमओयू के लिए पोर्ट एवं मरीन क्षेत्र के व्यवसायियों का भी आभार प्रकट किया।

श्री मोदी ने इस कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा कि 'चिप से शिप' तक के निर्माण द्वारा आत्मनिर्भरता हासिल कर भारत की समृद्धि का द्वार खोलना है। आज भावनगर 'समुद्र से समृद्धि' की ओर जाने का केन्द्र बना है।

उन्होंने कहा कि 2047 में विकसित भारत के संकल्प में आत्मनिर्भरता मुख्य है। उसकी विभावना पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि सभी दु:खों की एक ही दवा है, वह है आत्मनिर्भरता। भारत का समुद्री किनारा समृद्धि के द्वार खोलने वाला बनने वाला है। भारत सरकार सामुद्रिक विरासत के भारत के पुरातन गौरव को फिर से हासिल करने के लिए मरीन क्षेत्र की नीतियों में परिवर्तन ला रही है।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत का कोई दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन है, तो वह दसरे देशों पर निर्भरता है। जितनी विदेशी निर्भरता, उतनी देश की विफलता। विश्व में शांति, स्थिरता तथा समृद्ध के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हम 140 करोड़ देशवासियों का भविष्य दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। जब अन्यों पर निर्भरता भारत के आत्मसम्मान-स्वाभिमान पर प्रहार समान है, तब हमें विश्व बंधुत्व की भावना से 'आत्मनिर्भर भारत' के मंत्र को साकार करना है।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस मंत्र को साकार करने के लिए समग्र देशवासियों को एक भारत-श्रेष्ठ भारत के ध्येय के साथ कार्य करना होगा। गुजरात के व्यापारी भी उनकी दुकान पर 'गर्व से कहो, यह स्वदेशी है' के स्टिकर लगाकर आत्मनिर्भर भारत की अलख को अधिक मजबूत बनाएं।

उन्होंने आगे कहा कि पोर्ट लेड उद्योग को गति देने तथा क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए मुंबई इंटरनेशनल क्रूज स्टेशन का लोकार्पण हुआ है। गुजरात में भी पोर्ट विकास के अनेक कार्य गति-प्रगति में हैं। गुजरात में भी अलंग के साथ अनेक स्थानों पर शिप बिल्डिंग तथा रिसाइकलिंग के कार्य विकसित हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दुनिया के समक्ष टट्टार खड़ा रहना होगा। भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने लाइसेंस तथा कोटा राज में देश के मैरीटाइम के इकोसिस्टम को ठप कर डाला था। पूर्व में विदेशी जहाजों को किराए पर रखना हमारी मजबूरी बन गया था। केवल 5 प्रतिशत ही व्यवसाय रह गया था। भारत विदेशी शिपिंग कंपनियों को हर वर्ष 75 बिलियन (6 लाख करोड़) किराए के रूप में चुकाता था।

'टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड एनेस्थीसिया केयर' की थीम के साथ तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थिसियोलॉजिस्ट के वार्षिक सम्मेलन 'आईएसएसीओएन गुजरात 2025' में शामिल हुए

गांधीनगर, 20 सितंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को अहमदाबाद में इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थिसियोलॉजिस्ट के वार्षिक सम्मेलन 'आईएसएसीओएन गुजरात 2025' का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार अंतिम छोर के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्ड नागरिकों के लिए वरदान बन गया है। इस योजना से नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, जिससे नागरिकों का जीवन सुखमय हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी से जान बचाने का जो काम हो रहा है, वह प्रशंसनीय है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए तथा राज्य के नागरिकों को उसका लाभ किस प्रकार पहुंचाया जा सकता है, इस संबंध में डॉक्टरों से प्राप्त सुझावों का स्वागत किया।

उल्लेखनीय है कि इस तीन दिवसीय सम्मेलन में तकनीक आधारित एनेस्थीसिया देखभाल की थीम के अंतर्गत अत्याधानुक मॉनिटरिंग सिस्टम, रीयल टाइम एनेस्थीसिया की निगरानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ऑटोमेशन, ऑपरेशन के दौरान जटिलताओं का एआई आधारित पूवार्नुमान और पेशेंट सेफ्टी के लिए नई तकनीक सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा और गोष्ठी आयोजित की जाएगी।

इस अवसर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के डॉ. अनिल नायक, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थिसियोलॉजिस्ट (आईएसए) गुजरात राज्य शाखा के अध्यक्ष डॉ. दीपक मिस्त्री और डॉ. अतुल गांधी सहित चिकित्सा जगत के कई विशेषज्ञ और डॉक्टर मौजूद रहे।

मणिपुर में अज्ञात हमलावरों ने असम राइफल्स पर किया हमला, मेइती और कुकी-जो संगठनों ने जताया कड़ा विरोध

मणिपुर के बिश्नुपुर जिले में शुक्रवार को असम राइफल्स के जवानों पर घातक हमला होने के बाद शनिवार को मेइती और कुकी-जो संगठनों ने इसे कड़ी निंदा की है। घटना तब हुई जब असम राइफल्स का एक पैरामिलिट्री काफिला इम्फाल वेस्ट से बिश्नुपुर की ओर जा रहा था।

इस दौरान 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नंबोल सबाल लाइकाई क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने वाहन पर फायरिंग की। इस हमले में कम से कम दो जवान शहीद हुए जबकि पांच अन्य घायल हो गए।

हमले में शहीद हुए जवानों की पहचान नायक सूबेदार श्याम गुरूंग और रायफलमैन रंजीत सिंह कश्यप के रूप में हुई है। घायल जवानों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

कुकी-जो काउंसिल (KZC) ने इस हमले को "कायरतापूर्ण और बेरहमी से किया गया हमला" करार देते हुए निंदा की। काउंसिल ने अपने बयान में कहा कि यह घटना उन क्षेत्रों में हुई जहाँ विशेष सशस्त्र बल (AFSPA) की कोई शक्ति लागू नहीं है। उन्होंने कहा, "हिंसा, भेदभाव और उत्पीड़न के लगातार मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मेइती समुदाय के साथ शांति और सहअस्तित्व अब संभव नहीं रहा।"

स्थानीय लोगों ने किया विरोध

घटना के अगले दिन, शनिवार सुबह, बिश्नुपुर जिले के सबाल लाइकाई के स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फायरिंग में दो जवानों की जान गई और पांच घायल हुए, और यह हमला नागरिकों के लिए भी खतरा बन सकता था। एक स्थानीय ने कहा, "हमने इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा की। सुरक्षा बलों पर हमला न केवल जवानों के लिए, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी खतरा है।"

बता दें कि 21 सितंबर, 1949 को मणिपुर का भारत संघ में विलय हुआ था। लेकिन इस विलय को लेकर कई घाटी-आधारित उग्रवादी गुट अब भी आपत्ति जताते हैं और हर साल इस दिन विरोध दर्ज कराते हैं। इस वर्ष भी इन संगठनों ने बंद का आ'ान किया है और इसी से पहले शुक्रवार को असम राइफल्स के वाहन को निशाना बनाया गया।

हमले के बाद से क्षेत्रीय तनाव की आशंका

बिश्नुपुर, मेइती बहुल घाटी जिला, पहाड़ी जिले चुराचंद्रपुर से सटा हुआ है, जहाँ आदिवासी समुदाय बहुसंख्यक हैं।

भारतीय नौसेना और ग्रीस की हेलेनिक नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भूमध्य सागर में संपन्न हुआ

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना और ग्रीस की हेलेनिक नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का पहला आयोजन 18 सितंबर 2025 को भूमध्य सागर में

संपन्न हुआ, जो भारत और ग्रीस के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया गया। इसका पहला बंदरगाह चरण 13 से 17 सितंबर 2025 तक सलामीस नौसेना बेस पर आयोजित किया गया, और उसके बाद 17 और 18 सितंबर 2025 को समुद्री चरण आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंद ने किया।

बंदरगाह चरण के दौरान, दोनों नौसेनाओं के कर्मियों ने आपसी समझ और तालमेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई तरह की गतिविधियों में भाग लिया। प्रमुख कार्यक्रमों में परिचालन को मजबूत करने के लिए क्रॉस-डेक दौरे, चालक दल के बीच पेशेवर बातचीत और हेलेनिक नौसेना के एली क्लास फ्रिगेट एचएस थेमिस्टोकल्स पर आयोजित प्री-सेल सम्मेलन शामिल थे। जहाज पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में ग्रीस में भारत के राजदूत श्री रुद्रेंद्र टंडन, सलामिस नौसेना बेस के कमांडर कमोडोर स्पाइरिडॉन मेंटिस और हेलेनिक नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों और उनके परिवारों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम ने भारत की समृद्ध परंपराओं को प्रदर्शित किया और दोनों समुद्री बलों के बीच संबंधों को मजबूत किया। इसके अतिरिक्त, जहाज पर उपस्थित लोगों ने एक्रोपोलिस की पवित्र चट्टान का दौरा किया।

समुद्री चरण में दोनों नौसेनाओं की इकाइयों के बीच जटिल समुद्री युद्धाभ्यास और सामरिक अभ्यास हुए, जिनमें रात्रिकालीन वीबीएसएस ऑपरेशन, समुद्र में पुनःपूर्ति प्रक्रियाएँ, संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्ध, समन्वित गन फायरिंग और क्रॉस-डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन शामिल थे, जिससे अंतर-संचालन क्षमता में वृद्धि हुई। इन अभ्यासों ने न केवल दोनों नौसेनाओं के पेशेवर कौशल को प्रमाणित किया, बल्कि चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों में संयुक्त रूप से संचालन करने की उनकी क्षमता को भी उजागर किया।

इस प्रथम द्विपक्षीय अभ्यास का सफल आयोजन समुद्री सुरक्षा और सहयोगात्मक भागीदारी पर भारत और ग्रीस के बीच बढ़ते समन्वय को दर्शाता है। वैश्विक समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में दोनों देशों के साझा हित हैं। इस सहयोग ने सर्वोत्तम विधियों को साझा करने, अंतर-संचालनीयता विकसित करने और दोनों नौसेनाओं के बीच पेशेवर तालमेल बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया।

अभ्यास के समापन के बाद, आईएनएस त्रिकंद भूमध्य सागर में अपनी तैनाती के अगले चरण के लिए आगे बढ़ गया।

आंगनवाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं ने 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत कार निकोबार में पोषण के महत्व को प्रदर्शित किया

कार निकोबार स्थित बिशप जॉन रिचर्डसन अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल में पोषण माह 2025 का औपचारिक शुभारंभ 17 सितंबर 2025 को हुआ। कार्यक्रम की शुरूआत सीडीपीओ के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें 8वें राष्ट्रीय पोषण माह और स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं ने संतुलित आहार पर एक लघु नाटिका के माध्यम से पोषण के महत्व को दर्शाया। स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सहयोगी विभागों ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने में एकजुट होने पर सहमति व्यक्त की।

सीडीएस 22 सितंबर 2025 को त्रि-सेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी कार्यशाला (टी-सैट्स) का उद्घाटन करेंगे

(जीएनएस)।

सशस्त्र बलों और भारत के शैक्षणिक संस्थानों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने और सहयोग को मजबूत करने की कोशिश में, 22 से 23 सितंबर 2025 तक मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में एक त्रि-सेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी कार्यशाला (टी-सैट्स) आयोजित की जाएगी। 22 सितंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वे आधिकारिक संगोष्ठी पोर्टल के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रस्तुत 222 प्रतिक्रियाओं में से चुने गए नवाचारों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे।

भारतीय सेना द्वारा मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा के लिए महत्वपूर्ण विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए सेवा-अकादमिक अनुसंधान एवं विकास इको सिस्टम में तालमेल बनाना है। इस

प्रथम कार्यशाला का विषय है "विवेक व अनुसंधान से विजय" - बुद्धि और नवाचार के माध्यम से विजय।

इस कार्यक्रम में 200 से ज्यादा शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों और 50 अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के निदेशक और विभागाध्यक्ष, आईआईटी और टियर II व III तकनीकी संस्थानों के छात्र और तीनों सेनाओं के तकनीकी क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ एक साथ होंगे। यह सेनाओं की परिचालन आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक अत्याधुनिक अनुसंधान और तकनीकी समाधानों की पहचान, चर्चा और प्रचार के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा।

शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी भी 23 सितम्बर को कार्यशाला में भाग लेंगे।

स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) अभियान 2025

विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) अभियान 2025 के तहत विभिन्न पहलों के हिस्से के रूप में 20 सितम्बर 2025 को एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह

अभियान के तहत श्री आर.के. पटनायक, अपर सचिव/नोडल अधिकारी, श्री जी. पनमाई, अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता, श्रीमती राखी बिस्वास, अवर सचिव तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के मार्गदर्शन में सभी कमरों, अनुभागों और गलियारों की साफ-सफाई की गई। इस अभियान में सफाईकर्मियों के साथ-साथ विभाग और उससे संबद्ध कार्यालयों के अधिकारियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

झारखंड में पोषण माह अभियान में तेल और चीनी की खपत में कमी और 'पांच सूत्र - स्वर्णिम 1000 दिन' पहल पर प्रकाश डाला गया

(जीएनएस)।

आठवें पोषण माह 2025 का राज्य स्तर पर औपचारिक शुभारम्भ18 सितंबर 2025 को हो गया। इस शुभारम्भ कार्यक्रम का उद्घाटन अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सचिव श्री मनोज कुमार और समाज कल्याण निदेशक किरण पासी की गरिमामयी उपस्थिति में किया। इस शुभारम्भ में राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों, विकास भागीदारों, आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जो राज्य भर में जमीनी स्तर पर पोषण संबंधी पहलों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर, गणमान्य हस्तियों ने प्रमुख अभियान सामग्री का अनावरण किया, जिसमें दैनिक आहार में तेल और चीनी की खपत में कमी और "पांच सूत्र - स्वर्णिम 1000 दिन" पहल को बढ़ावा देने वाले पोस्टर शामिल थे। ये संचार सामग्री पोषण अभियान के अंतर्गत सामाजिक लामबंदी और सामुदायिक जागरूकता हेतु राज्य की रणनीति का केंद्रबिंदु हैं। झारखंड के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को एक सप्ताह के भीतर ये पोस्टर प्राप्त हो जाएंगे ताकि सामुदायिक स्तर पर व्यापक पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित की जा सके।

सम्पादकीय

पाक की चालबाजी हुई फेल

इन दिनों विश्व राजनीति में कौन किसके साथ खड़ा है, यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के प्रतिबंध समिति के सामने पाकिस्तान ने अपने सदाबहार मित्र चीन के साथ मिलकर बलूचिस्तान के विद्रोही गुटों बीएलए यानि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ आतंकी सूची में डलवाकर देश और विदेशों में उनकी यात्रा पर रोक लगवाने तथा उनकी संपत्तियों को जप्त करने के उद्देश्य से प्रस्ताव लाया कितु अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने उसके प्रस्ताव का विरोध करके दोनों के प्रयासों को असफल कर दिया। मजे की बात है कि पाकिस्तान ने बड़ी दौड़ धूप करके अमेरिका द्वारा इन दोनों संगठनों को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी संगठन (एसडीजीटी) की सूची में शामिल करके विदेशी आतंकी संगठन घोषित कराया था।

दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के मुताबिक मात्र उन संगठनों को ही यूएन प्रतिबंध समिति आतंकी सूची में डालता है जिनका अलकायदा और आईएसआईएस से संबंध हो। 1999 में जिस 1267 प्रस्ताव का प्रावधान किया गया था, उसका ईमानदारी से पालन किया होता तो तमाम आतंकी संगठनों या आतंकियों पर प्रतिबंध लग जाते और वे अपने सही ठिकाने यानि जेल में होते। लेकिन पाकिस्तान उन्हें अपना नागरिक बताकर अपने मित्र चीन से वीटो लगवा कर यूएन में बचा लेता है। यही है यूएन के स्थाई सदस्यों का दोहरा चरित्र।

असल में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें स्पष्ट रूप से दावा किया गया कि आईएसआईएस के अलकायदा तहरीके तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी), बीएलए और उसकी मजीद ब्रिगेड जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान से संचालित हो रहे हैं और वहीं से पाकिस्तान में सीमापार से हमले कर रहे हैं। यही नहीं पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने यह भी दावा किया कि आतंकवाद-पाकिस्तान की प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है और इसके लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को अपने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दायित्व को पूरा करना चाहिए।

पाकिस्तान और चीन के इस तर्क को अमेरिका उसके सहयोगी देशों ने खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड को अलकायदा और आईएसआईएस से संबंध का कोई प्रमाण नहीं है। यदि पाकिस्तान और चीन का यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता तो यह चीन और पाकिस्तान दोनों की बहुत बड़ी जीत होती। अमेरिका ने तो इससे पहले 2019 में भी बीएलए और मजीद ब्रिगेड को एसडीजीटी की सूची में नामित किया था।

सच तो यह है कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड ने न सिर्फ पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है बल्कि चीन भी उनसे बहुत परेशान है। चीन इन्हीं दोनों संगठनों के विरोध के कारण ग्वादर बंदरगाह को विकसित नहीं कर पा रहा है और इन्हीं दोनों संगठनों की वजह से बलूचिस्तान से खनिज पदार्थो की खुदाई कर पाने में सफल भी नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान की आर्मी ने चीन के इंजीनियरों की सुरक्षा के लिए इस राज्य को भयाक्रांत करने के उद्देश्य से ही क्रूरता की हदें पार कर दी हैं। बलूचिस्तान के लोग जितना पाकिस्तान की सेना और सरकार से घृणा करते हैं, उतना ही उन चीनी इंजीनियरों एवं चीन की कंपनी के कार्मियों से भी नफरत करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान को गलतफहमी हुई कि यदि बीएलए और मजीद ब्रिगेड को यूएन प्रस्ताव के तहत आतंकी घोषित करने में अमेरिका मदद कर देगा तो उसके सहयोगी ब्रिटेन और फ्रांस भी साथ दे सकते हैं। कितु उसकी यह चालबाजी काम नहीं आई। पाकिस्तान की सक्रियता का सबसे बड़ा कारण है कि उसे यह गलतफहमी हो गई है कि भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक, सुरक्षा और खुफिया तंत्र सहयोग के क्रम खत्म हो चुके हैं। वह इतनी सरल बात भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि इन दिनों नई दिल्ली और वाशिंगटन डीसी के जो संबंध खराब दिख रहे हैं वे असल में दोनों देशों के स्थाई संबंध नहीं हैं, बल्कि अस्थाई दौर है।

एनसीएच : उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार 2025 के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर जीएसटी शिकायत निवारण को बेहतर बनाता है

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार 2025 के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर जीएसटी शिकायत निवारण को बेहतर बनाता है

एनसीएच ने समर्पित जीएसटी उप-श्रेणी के माध्यम से उपभोक्ता सशक्तिकरण को मजबूत किया

प्रविष्टि तिथि: 20 एएढ 2025 11:42अटु८ ढक्ह ऊै

उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) को केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56 वीं बैठक के दौरान अनुमोदित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार 2025 के साथ संरेखित करने के लिए कदम उठाए हैं और यह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2025 के संबोधन में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के अनुसार है।

22.09.2025 से प्रभावी संशोधित जीएसटी शुल्कों, दरों और छूटों के कार्यान्वयन के बाद एनसीएच पर अपेक्षित उपभोक्ता प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए, आईएनजीआरएएम पोर्टल पर एक समर्पित श्रेणी शुरू की गई है। इस श्रेणी में ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ई-कॉमर्स, एफएमसीजी और अन्य सहित प्रमुख उप-श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें जीएसटी से संबंधित शिकायतें दर्ज की जाएंगी।

इस पहल की तैयारी के लिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधिकारियों द्वारा 11.09.2025 को एक उद्घाटन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया ताकि एनसीएच परामर्शदाताओं को जीएसटी से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान करने में योग्य बनाया जा सके। हाल ही में, सचिव (उपभोक्ता मामले) की अध्यक्षता में 17.09.2025 को एक हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की गई जिसमें प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु कंपनियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, प्रतिभागियों से विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आग्रह किया गया।

यह हेल्पलाइन इस क्षेत्र में उपभोक्ता शिकायतों से प्राप्त आंकड़ों और जानकारियों को संबंधित कंपनियों, सीबीआईसी और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ साझा करेगी ताकि संबंधित कानूनों के तहत समय पर कार्रवाई संभव हो सके। इस पहल से जीएसटी अनुपालन को मजबूत करने और उपभोक्ताओं को निष्पक्ष बाजार प्रथाओं में सक्रिय हितधारक बनने के लिए सशक्त बनाकर एक सहभागी शासन मॉडल को बढ़ावा मिलने की आशा है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (६६६.ड्ड्ल्ल२ौ१ँ'स्र'ल्ली.ड्ढ५.ल्ल) देश भर के उपभोक्ताओं के लिए मुकदमे-पूर्व चरण में शिकायत दर्ज कराने हेतु एकीकृत केंद्र के रूप में उभरी है। उपभोक्ता अब टोल-फ्री नंबर 1915 या एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनजीआरएएम) के माध्यम से 17 भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मैथिली, संथाली, बंगाली, उड़िया, असमिया और मणिपुरी सहित) में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह सर्व-चैनल आईटी-सक्षम प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल और उमंग ऐप सहित कई पंजीकरण मोड का समर्थन करता है, जो उपभोक्ताओं को सुविधा और सुगमयता प्रदान करता है।

पिछले कुछ वर्षों में, एनसीएच निजी कंपनियों, नियामकों, लोकपाल और सरकारी एजेंसियों सहित 1,142 कन्वर्जेंस भागीदारों के साथ सहयोग से एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हुआ है, जिससे केंद्रीकृत और जल्द शिकायत समाधान संभव हुआ है। पारदर्शी ट्रैकिंग और समाधान के लिए प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट डॉकेट नंबर दिया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में प्रति माह एक लाख से ज्यादा शिकायतें आती हैं , जो बढ़ते उपभोक्ता विश्वास को दर्ज कराता है।

एनसीएच के तकनीकी परिवर्तन ने इसकी कॉल-हैंडलिंग क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। एनसीएच को प्राप्त कॉलों की संख्या दिसंबर 2015 में 12,553 से दस गुना से भी अधिक बढ़कर दिसंबर 2024 में 1,55,138 हो गई है। यह अभूतपूर्व वृद्धि हेल्पलाइन में उपभोक्ताओं के बढ़ते विश्वास को सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार, प्रति माह दर्ज होने वाली शिकायतों की औसत संख्या 2017 में 37,062 से बढ़कर 2025 में 1,70,585 हो गई है। डिजिटल माध्यमों की शुरूआत के साथ, हेल्पलाइन पर लगभग 65 प्रतिशत उपभोक्ता शिकायतें ऑनलाइन और डिजिटल माध्यमों से दर्ज की जाती हैं।

महान अभिनेता, निर्देशक और निमार्ता मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए 71वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के दौरान वर्ष 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा

केरल से लेकर दुनिया भर के दर्शकों तक, श्री मोहनलाल के कार्यों ने हमारी संस्कृति का उत्सव मनाया है और हमारी आकांक्षाओं को परिलक्षित किया है, उनकी विरासत भारत की रचनात्मक भावना को प्रेरित करती रहेगी: श्री अश्विनी वैष्णव

(जीएनएस)।

दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर, भारत सरकार ने आज घोषणा की कि श्री मोहनलाल को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महान अभिनेता, निर्देशक और निमार्ता को भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। यह पुरस्कार उन्हें 23 सितंबर, 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज भारतीय सिनेमा में श्री मोहनलाल के असाधारण योगदान के सम्मान में पुरस्कार की घोषणा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की।

श्री मोहनलाल की उल्लेखनीय सिनेमा यात्रा पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। उनकी बेजोड़ एवं बहुमुखी प्रतिभा और निरंतर कड़ी मेहनत ने भारतीय फिल्म इतिहास में स्वर्णिम मानक स्थापित किया है।

श्री मोहनलाल के विषय में

श्री मोहनलाल विश्वनाथन नायर (जन्म 21 मई 1960, केरल) एक प्रशंसित भारतीय अभिनेता, निमार्ता और पार्श्व गायक हैं, जिन्हें मलयालम सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। वह व्यापक रूप से एक "पूर्ण अभिनेता" के रूप में जाने जाते हैं। लगभग पांच दशकों के अपने करियर में वह 360 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिन्होंने किरीडम, भारतम, वानप्रस्थम, दृश्यम और ऐसी अन्य कई फिल्में हैं जिनमें उन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है।

श्री मोहनलाल ने भारत और विदेश में कई अन्य सम्मानों के साथ पांच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और केरल में कई राज्य फिल्म पुरस्कार जीते हैं। 1999 में उनकी फिल्म वानप्रस्थम कान्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित हुई, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली।

सिनेमा के अलावा, उन्हें 2009 में भारतीय प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत सरकार द्वारा उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। आज, मोहनलाल भारत के सबसे सम्मानित सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक हैं, जिन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा, विनम्रता और विश्व सिनेमा में उनके स्थायी योगदान के लिए सराहा जाता है।

दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विषय में

भारतीय सिनेमा में दादासाहेब फाल्के के योगदान को याद करने के लिए भारत सरकार ने 1969 में देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया था, जिन्होंने 1913 में भारत की पहली फुल-लेंथ फीचर फिल्म, राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित पुरस्कार विजेताओं को 'भारतीय सिनेमा के विकास और प्रगति में उनके उत्कृष्ट योगदान' के लिए सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

श्री मिथुन चक्रवर्ती

श्री शंकर महादेवन

श्री आशुतोष गोवारिकर

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत में लॉजिस्टिक्स लागत के आकलन पर रिपोर्ट जारी की, जिससे डेटा-आधारित लॉजिस्टिक्स योजना को मजबूती मिलेगी

यह दशक मेक इन इंडिया का: सरकार ने प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए व्यापक लॉजिस्टिक्स लागत के आकलन का अनावरण किया

(जीएनएस)।

"मेक इन इंडिया" के एक दशक पूरे होने के उपलक्ष्य पर, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत में लॉजिस्टिक्स लागत के आकलन पर रिपोर्ट जारी की। पहली बार, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत का एक व्यापक और वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त किया गया अनुमान होगा, जिसमें द्वितीयक आंकड़ों को राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणों के साथ मिलाकर एक मिश्रित पद्धति का उपयोग किया जाएगा। यह पहल राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) के उस आदेश का अनुसरण करती है, जिसके अंतर्गत लॉजिस्टिक्स लागतों को मापने और उन्हें वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप मानकीकृत करने हेतु एक समान ढांचा स्थापित किया जाना है।

श्री गोयल ने इस विषय पर प्रकाश डाला कि सरकार ने लॉजिस्टिक्स को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और भारत में व्यापार की लागत कम करने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से तैयार किए गए अध्ययन और रिपोर्ट लॉजिस्टिक्स लागत से जुड़े प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद कर रहे हैं। प्रत्येक हामोर्नाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर (एचएसएन) कोड को संबंधित मंत्रालय से जोड़ने जैसे प्रयास

समन्वय को सुव्यवस्थित करते हैं और मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वाताओं में भारत की स्थिति को मजबूत करते हैं। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक का निर्माण, एडीबी के सहयोग से स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत राज्य और शहर लॉजिस्टिक्स योजनाओं का कार्यान्वयन, और एनआईसीडीसी एवं अन्य एजेंसियों की ओर से संचालित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्देश्य मौजूदा सुविधाओं का आकलन करना, परिवहन और कनेक्टिविटी में सुधार करना और कमियों को घटाना है। ये उपाय, जीएसटी कार्यान्वयन और युक्तिकरण जैसे सुधारों के साथ, लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन देने के चल रहे प्रयासों के केंद्र में हैं।

अब तक, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को अक्सर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता था, और आमतौर पर बाहरी अध्ययनों या आंशिक डेटासेट से प्राप्त जीडीपी के 13-14% के आंकड़े बताए जाते थे। इससे विसंगत अनुमान सामने आते थे, जिससे नीति निमार्ताओं और वैश्विक हितधारकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती थी। एनसीएईआर की ओर से डीपीआईआईटी के लिए तैयार किए गए वर्तमान आकलन के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत कुल जीडीपी का लगभग 7.97% होने का अनुमान है।

यह रिपोर्ट कई परिवहन साधनों, उत्पाद श्रेणियों और फर्म आकारों में लॉजिस्टिक्स लागतों को शामिल करके एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। यह प्रति टन-किलोमीटर माल ढुलाई लागत का अनुमान भी देती है और क्षमता बढ़ाने में बहु-विधता की भूमिका पर प्रकाश डालती है। साक्ष्य-आधारित मार्गदर्शन देकर, यह अध्ययन प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के भारत के प्रयासों को मजबूत करता है और देश को एक वैश्विक लॉजिस्टिक्स केंद्र के तौर पर स्थापित करने के व्यापक दृष्टिकोण में सहयोग करता है।

बीते पांच वर्ष के अनुमान बताते हैं कि गैर-सेवा उत्पादन की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत की बढ़ोतरी दर धीरे-धीरे धीमी हो रही है। इस सुधार का श्रेय प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, समर्पित माल ढुलाई गलियारे, भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, एकीकृत चेक पोस्ट, एकीकृत रसद इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) का विकास और रसद दक्षता संवर्धन कार्यक्रम (लीप) जैसी पहलों को दिया जा सकता है।

नोएडा और मथुरा के आसमान में देर रात क्या दिखा? मोबाइल में कैद हुआ आसमानी रहस्य

(जीएनएस)।

19 और 20 सितंबर की दरम्यानी रात दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम समेत मथुरा में शुक्रवार रात आसमान में एक अद्भुत खगोलीय घटना देखने को मिली। एक तेज चमकते उल्कापिंड (टीइड्ड१) ने दिल्ली-एनसीआर और मथुरा के लोगों को हैरान कर दिया। यह घटना 20 सितंबर 2025 की भारतीय समयानुसार रात 1 बजकर 52 मिनट पर रिकॉर्ड हुई।

आसमान में आग का गोला

प्रत्यक्षदर्शियों समेत वनइंडिया के चीफ सब एडिटर सिद्धार्थ पुरोहित के मुताबिक, अचानक आसमान में चमकदार रोशनी की एक लंबी धार नजर आई, और फिर ऐसा लगा जैसे उल्कापिंड हवा में फट गया हो। यह नजारा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मथुरा और अलीगढ़ समेत कई शहरों में देखा गया। सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो वायरल हो गए, जिनमें आसमान में आग का गोला चमकता और फिर छोटे-छोटे चमकीले टुकड़ों में टूटता दिखाई दे रहा है।

एक्सपर्ट्स ने क्या बताया?

खगोल विज्ञान विशेषज्ञों ने बताया कि यह घटना संभवतः बोलिड थी - यह एक खास प्रकार का उल्कापिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने के बाद तेज रोशनी के साथ टूट जाता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक-

- उल्कापिंड आम तौर पर जमीन पर पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं।
- इस घटना से किसी भी प्रकार के नुकसान की संभावना नहीं है।

दुर्लभ और रोमांचक नजारा

अमेरिकन मेट्योर सोसाइटी के अनुसार, सितंबर का महीना छोटे उल्कापिंडों के लिए सक्रिय समय होता है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के सामने इतने चमकीले उल्कापिंड का दिखना काफी दुर्लभ है।

कई लोगों ने देखा नजारा

दिल्ली-एनसीआर के कई लोगों ने बताया कि यह चमक कुछ सेकंड के लिए ही थी, लेकिन इतनी तेज थी कि शहर की रोशनी भी फीकी पड़ गई। कुछ लोगों ने हल्की गड़गड़ाहट की आवाज सुनने का भी दावा किया, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।

किसी नुकसान की रिपोर्ट नहीं

अधिकारियों ने साफ किया है कि इस घटना से कोई नुकसान नहीं हुआ है। आकाश देखने वालों ने इस दृश्य को "लाइफटाइम एक्सपीरियंस" बताया। इस खबर को लिखने वाले पत्रकार सिद्धार्थ घटना के वक्त मथुरा में थे। उन्होंने अपने फोन में भी इस घटना को मथुरा के भीड़-भाड़ वाले इलाके से रिकॉर्ड भी किया।

औद्योगिक पार्कों के मानकीकरण के लिए आईपीआरएस 3.0 आरम्भ

दशक भर से चल रहे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की कामयाबी के उत्सव के अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज औद्योगिक पार्कों की दक्षता आंकलन प्रणाली (पीआरएस) 3.0 का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग द्वारा एशियन डिवलपमेंट बैंक के सहयोग से तैयार की गई आंकलन प्रणाली का उद्देश्य भारत के औद्योगिक वातावरण को और अधिक मजबूत करना एवं औद्योगिक बुनियादी ढांचे के प्रतिस्पर्धी स्वरूप को विस्तार देना है। श्री गोयल ने बताया कि एनआईसीडीसी के अंतर्गत सरकार 20 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक पार्क एवं स्मार्ट सिटी विकसित कर रही है जिनमें से 4 का निर्माण पूरा भी हो चुका है। उनके अनुसार चार अन्य का निर्माण कार्य तेजी से जारी है और बाकी की निर्माण परियोजना नीलामी एवं टेंडरिंग के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आईपीआरएस 3.0 को लागू करने से देश भर में औद्योगिक पार्कों में सुविधाओं, बुनियादी ढांचे एवं उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को मानकीकृत करने एवं उनके आंकलन में सहायता मिलेगी। इस पहल से इसके भागीदारों को भरोसेमंद डेटा/आंकड़े प्राप्त हो पाएंगे, श्रेष्ठ प्रथाओं को प्रोत्साहन मिलेगा तथा विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद मिलेगी जिससे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम सुदृढ़ होगा तथा भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी।

साल 2018 में इसके पायलट/प्रायोगिक चरण और साल 2021 में शुरू किए गए आईपीआरएस 2.0 को आगे बढ़ाते हुए नए पैमानों के साथ तीसरे संस्करण को लागू किया गया है। इसमें वहनीयता, पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक संबंधी जुड़ाव, डिजिटल ढांचा, कौशल संपर्क एवं किरायेदारों की समस्याओं की संवेदनशीलता से सुनवाई जैसे तत्व भी शामिल हैं। पीआरएस 3.0 के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों का मानकीकरण करके उनका अगुआ, चुनौतीदाता एवं आंकांक्षी के रूप में वर्गीकरण किया जाएगा। यह वर्गीकरण प्रमुख संकेतकों के आंकलन के आधार पर किया जाएगा। इससे निवेशकों को पारदर्शी एवं विश्वसनीय सूचना प्राप्त होगी, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का बीजारोपण होगा एवं नीति निर्धारकों को लक्ष्यित दखल करने की दृष्टि प्राप्त होगी।

राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को इस पहल से अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पार्कों को निवेशकों के सामने पेश करने का अवसर, सुधार के लिए कमियों को पहचानने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार पैदा करने एवं अपने औद्योगिक वातावरण को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। इस कार्य से भारत और अधिक वहनीय एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धी निवेश स्थल के रूप में तेजी से अपनी हपचान बना पाएगा।

'स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2025' और विशेष अभियान 5.0 का आयोजन

(जीएनएस)।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) और पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब् ल् यूएस) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2025 के 9वें आयोजन (17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित) के उपलक्ष्य में, उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) स्वच्छता ही सेवा 2025 के तहत विभिन्न पहल कर रहा है। एसएचएस 2025 का विषय, "स्वच्छोत्सव", इस अवधि की उत्सव भावना को दशार्ता है और इसमें पांच विशेष क्षेत्रों पर ध् यान केंद्रित किया गया है:

स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (सीटीयू) का रूपांतरण: कठिन, प्रकाश विहीन और उपेक्षित स्थानों को समाप् त करना

स्वच्छ सार्वजनिक स्थान: सार्वजनिक क्षेत्रों में सामान्य सफाई और स्वच्छता गतिविधियाँ

सफाईमित्र सुरक्षा शिविर: स्वास्थ्य जांच और स्वच्छता कार्यकताओं के कल्याण के लिए एकल-खिड़की सेवा, सुरक्षा और सम्मान शिविर

स्वच्छ हरित उत्सव: पर्यावरण-अनुकूल और शून्य-अपशिष्ट उत्सव

स्वच्छता के लिए पहल : स्वच्छ सुजल गांव, अपशिष्ट से कला, स्वच्छ स्ट्रीट फूड, आरआरआर केंद्र, आदि।

इसके अलावा, स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित विशेष अभियान 5.0, दो अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक मनाया जाएगा। अभियान का शुरूआती चरण- 15 सितंबर से शुरू हो गया है और कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा।

इस अभियान के दौरान, डीओसीए निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है: सांसदों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी स्रोतों और पीएमओ से लंबित संदर्भों की पहचान। लंबित जन शिकायतों और अपीलों की समीक्षा। स्वच्छता अभियानों के लिए स्थलों का चयन। अनावश्यक सामग्रियों और कचरे का निपटान। रिकॉर्ड और स्थान प्रबंधन। डीओसीए और देश भर में इसके अधीनस्थ/संबद्ध/स्वायत्त कार्यालयों द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिदेर्शों के अनुसार ई-कचरे का निपटान भी किया जाएगा।

शुरूआती गतिविधियों के एक हिस् से के रूप में, उपभोक्ता मामले सचिव की अध्यक्षता में 16.09.2025 और 17.09.2025 को एसएचएस 2025 और विशेष अभियान 5.0 की तैयारियों का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। इससे पहले, उपभोक्ता मामले विभाग के सलाहकार (लागत) की अध्यक्षता में 10.09.2025 को अधीनस्थ/संबद्ध/स्वायत्त कार्यालयों के नोडल अधिकारियों के साथ सक्रिय भागीदारी पर चर्चा करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक भी आयोजित की गई थी।

उपभोक्ता मामले विभाग, बीआईएस, एनटीएच, एनसीसीएफ, एनसीडीआरसी और सभी आरआरएसएल के साथ मिलकर इन अभियानों की सफलता सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से हिस् सा ले रहा है। स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि के लिए विभिन्न कार्यालयों में स्वच्छता शपथ दिलाई गई है। इस अभियान के दौरान, अधिकारी और कर्मचारी श्रमदान गतिविधियाँ करेंगे।

स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का समापन 2 अक्टूबर 2025 (स्वच्छ भारत दिवस) को राष्ट्रव्यापी श्रमदान के साथ होगा, जिसमें महात्मा गांधी की विरासत का सम्मान किया जाएगा और स्वच्छता को जीवन का एक तरीका बनाने के दृष्टिकोण को सुदृढ़ किया जाएगा।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

वडोदरा डिवीजन स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान अंतर्गत वॉलीबॉल लीग का सफल आयोजन

'स्वच्छता ही सेवा' (SHS) 2025 पूरे देश में 17 सितम्बर से प्रारंभ हुआ, जो 2 अक्टूबर, 2025 को गांधी जयंती के अवसर पर समाप्त होगा। इस वर्ष के अभियान का थीम 'स्वच्छोत्सव' रखा गया है। इस अभियान में कार्यस्थलों, आवासीय क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई, सफाई मित्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा, पर्यावरण मित्र एवं शून्य अपशिष्ट कार्यक्रम और स्वच्छता के प्रति व्यापक जन जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इसी कड़ी में प्रतिभाओं को मंच देने और खेल कूद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, वडोदरा डिवीजन स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आज एक भव्य वॉलीबॉल लीग का सफल आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय रोमांचक टूनार्मेंट में मंडल के कर्मचारियों और खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह भरा।

इस अवसर पर वडोदरा मंडल के डिवीजनल रेलवे मैनेजर श्री राजू भडके, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री नीरज धमीजा, वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर (पावर) श्री प्रदीप मीणा, वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (समन्वय) श्री सुमित ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं रेलवे कर्मचारी उपस्थित रहे।

सुबह से शुरू हुए इस टूनार्मेंट में मंडल के विभिन्न विभागों ने 12 टीमों ने हिस्सा लिया। लीग-कम-नॉकआउट प्रारूप में खेले गए मैचों में खिलाड़ियों ने अपनी असाधारण प्रतिभा और खेल भावना का परिचय दिया। हर मैच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जिससे दर्शकों का जोश लगातार बढ़ता रहा। फाइनल मुकाबला विशेष रूप से रोमांचक रहा, जहाँ अधिकारियों की टीम ने इंजीनियर विभाग को 2-0 के स्कोर से हराकर खिताब अपने नाम किया।

इस सफल आयोजन पर वडोदरा डिवीजन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रदीप मीणा ने कहा, "हम इस भव्य वॉलीबॉल लीग की सफलता से बेहद खुश हैं। हमारा उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करना और उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने के लिए प्रेरित करना है। हमें उम्मीद है कि इस तरह के आयोजन भविष्य में भी होते रहेंगे।"

लीग के अंत में एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। विजेता टीम को ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, उपविजेता टीम को भी ट्रॉफी प्रदान की गई।

एसोसिएशन ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग विशेष अभियान 5.0 के लिए तैयारी चरण की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं

तैयारी चरण की प्रगति की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारियों की तीसरी बैठक आयोजित

इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान और प्रचार-प्रसार किया गया, जिसमें 307 ट्वीट, 45 पीआईबी वक्तव्य और सोशल मीडिया पर #Specialcampaign5 का प्रचार-प्रसार हुआ

मंत्रालय/विभाग अभियान को संपूर्ण करेंगे

(जीएनएस)।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को नोडल विभाग बनाकर सरकार की ओर से शुरू किए गए विशेष अभियान 5.0 ने अपने तैयारी चरण में उल्लेखनीय गति प्राप्त की है। विशेष अभियान 5.0,2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक कार्यान्वयन चरण में प्रवेश करेगा, जिसके पहले 15 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक तैयारी चरण जारी है।

इस चरण के दौरान, मंत्रालयों/विभागों ने अपने-अपने संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों में स्थित अभियान कार्यालयों में नोडल अधिकारियों को नामित किया और उन्हें अभियान में उनकी भूमिकाओं को लेकर प्रशिक्षित किया। इसमें क्षेत्रीय कार्यकताओं को संगठित करना, लंबित मामलों की पहचान करना, स्वच्छता अभियान के लिए कार्यालयों की सूची को अंतिम रूप देना, निपटाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक/ऑटोमोबाइल/कार्यालय स्क्रैप की मात्रा का आकलन करना और उनके निपटान की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देना जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल थीं। उन्होंने कार्यालय स्थानों के विस्तार, डिजिटलीकरण प्रक्रियाओं, स्क्रैप निपटान प्रक्रियाओं, स्वच्छता प्रोटोकॉल, समावेशी उपायों और अभिलेखों की छंटाई तथा ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण हेतु अभिलेख प्रबंधन प्रक्रियाओं की योजनाएं भी शुरू कीं।

विशेष अभियान 5.0 की प्रगति की निगरानी एक समर्पित वेब-पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सभी मंत्रालय/विभाग इस अभियान के प्रारंभिक चरण के लक्ष्य विशेष अभियान 5.0 वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे। प्रारंभिक चरण 15 सितंबर 2025 को शुरू हुआ। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार विशेष अभियान 5.0 के तहत 10 से 14 अक्टूबर 2025 तक "सुशासन और अभिलेख प्रदर्शनी" का आयोजन करेगा। यह प्रदर्शनी विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के ऐतिहासिक विकास पर केंद्रित होगी और इसमें इन मंत्रालयों द्वारा योगदान किए गए महत्वपूर्ण अभिलेखीय अभिलेखों को प्रदर्शित किया जाएगा।

स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 5.0 के नोडल अधिकारियों के साथ तीसरी बैठक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में प्रारंभिक चरण की गतिविधियों की समीक्षा की गई। इस बैठक में 84 मंत्रालयों/विभागों के 190 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने एससीडीपीएम 5.0 पोर्टल का प्रदर्शन किया और नोडल अधिकारियों को डेटा अपलोड करने और लक्ष्यों की निगरानी के बारे में मार्गदर्शन दिया। कई मंत्रालयों/विभागों ने भी अपनी प्रारंभिक प्रगति और योजनाओं को साझा किया: रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), संस्कृति मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने विशेष अभियान 4.0 की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित किया और विशेष अभियान 5.0 की योजनाएं प्रस्तुत कीं।

इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने और अभियान की पैरवी करने का काम किया जा रहा है। अब तक #रस्र्ीू'उेंर्ॅल्ल5 के तहत 307 ट्वीट और 45 पीआईबी वक्तव्य जारी किए जा चुके हैं, जो विशेष अभियान 5.0 में व्यापक भागीदारी के संकेत हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग सुशासन सप्ताह 2025 की गतिविधियों के हिस्से के रूप में विशेष अभियान 5.0 के तहत सर्वोत्तम प्रथाओं का एक संग्रह प्रस्तुत करेगा।

यूटीएस ऐप तथा एटीवीएम से टिकट लेना हुआ और भी आसान

अब अनारक्षित टिकट के लिए लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में अनारक्षित टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुगम बना दिया गया है। अब यात्रियों को जनरल टिकट (अनारक्षित टिकट) के लिए लंबी लाइनों में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है।

रेलवे ने यात्रियों को दो सुविधाएं प्रदान की हैं झ यूटीएस मोबाइल ऐप (UTS App) और स्वचालित टिकट वितरण मशीन (ATVM)। इन दोनों माध्यमों से यात्री स्वयं टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।

यूटीएस ऐप (UTS APP) की विशेषताएं:

यात्री अपने मोबाइल फोन से घर बैठे ही टिकट बुक कर सकते हैं।

यात्रा टिकट, सीजन टिकट तथा प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा उपलब्ध।

भुगतान के लिए UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड तथा R-Wallet का विकल्प उपलब्ध।

R-Wallet रिचार्ज पर 3% बोनस राशि प्राप्त करें।

टिकट खिड़की पर लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं।

समय और पैसे की बचत।

छुट्टे पैसे की समस्या नहीं।

पेपरलेस टिकट की सुविधा, जो पर्यावरण के अनुकूल है।

एटीवीएम (ATVM) की विशेषताएं:

यात्री स्टेशन पर स्थित ATVM मशीन से स्वयं टिकट बुक कर सकते हैं।

यात्रा टिकट, सीजन टिकट तथा प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा उपलब्ध।

भुगतान के लिए वढक दफ कोड तथा रेलवे स्मार्ट कार्ड की सुविधा।

रेलवे स्मार्ट कार्ड रिचार्ज पर 3% बोनस राशि प्राप्त करें।

टिकट खिड़की की लंबी लाइनों से मुक्ति।

समय और पैसे दोनों की बचत।

छुट्टे पैसे की समस्या नहीं।

पश्चिम रेलवे यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे इन आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाएं और अपनी यात्रा को सरल एवं सुविधाजनक बनाएं। यूटीएस ऐप और एटीवीएम के माध्यम से बुकिंग कर यात्री न केवल समय बचा सकते हैं, बल्कि डिजिटल इंडिया अभियान में भी सहभागी बन सकते हैं।

रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सौगात! रेलनीर की कीमत में कटौती, अब 15 में नहीं इतने में मिलेगा पानी

(जीएनएस)। केंद्रीय सरकार ने उपभोक्ताओं को सीधा लाभ पहुंचाने और जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में राहत देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी दिशा में सरकार ने रेल नीर की कीमतों में GST कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का निर्णय लिया है।

इससे आम जनता को दैनिक जरूरतों की वस्तुओं पर आर्थिक राहत मिलेगी और महंगाई के दबाव को कम करने में मदद होगी। सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि सभी वर्गों के लोग आसानी से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल का उपयोग कर सकें।

RÔil Neer price cut

अब कितने का मिलेगा?

रेलवे बोर्ड के ताजा सर्कुलर के अनुसार रेलवे और IRCTC में बिकने वाले पैकेज्ड वॉटर की कीमतों में कटौती की गई है:

1 लीटर की बोतल: ₹15 से घटाकर ₹14 (1 रुपए की कमी)

500 मिलीलीटर की बोतल: ₹10 से घटाकर ₹9 (1 रुपए की कमी)

इसका मतलब है कि दोनों कैपेसिटी की बोतलों पर 1-1 रुपए की कीमत कम कर दी गई है, और यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।

क्यों घटाई गई रेलनीर की कीमत?

रेल मंत्रालय ने यह कटौती इसलिए की है ताकि GST कम किए जाने का सीधा लाभ यात्रियों और उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। इसके तहत 1 लीटर की RÔil Neer बोतल की कीमत ₹15 से घटाकर ₹14 और 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत ₹10 से घटाकर ₹9 कर दी गई है। इस कदम से यात्रियों को पैकेज्ड पानी सस्ता उपलब्ध होगा और उनकी जेब पर बोझ कम होगा।

ये भी पढें: फ्र्ॅीरॅ-डं१ल्लस्र१८ फ्रं छल्ली: देश की सबसे लंबी दोहरी रेल सुरंग का निर्माण पूरा, जानिए अब कितना काम बचा

सरकार ने हाल ही में कई जरूरी चीज पर कम की है GST

भारत सरकार ने हाल ही में रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं पर GST दरों में बड़ी कटौती की है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सीधे आर्थिक राहत देना और घरेलू मांग को बढ़ावा देना है। अब कई आवश्यक सामानों पर GST 12% और 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे रिटेल दुकानों पर इन उत्पादों की कीमतों में तुरंत कमी दिखाई देगी, जो घर के मासिक खर्च को कम करने में मदद करेगी। दुकानदारों को आगामी 22 सितंबर से उन सभी वस्तुओं के नए दाम दुकान के बाहर प्रदर्शित करने होंगे जिनकी GST दरों में बदलाव किया गया है।

साबरमती रेलवे अस्पताल में ₹स्वस्थ नारी, स्वस्थ परिवार₹ के अंतर्गत महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य पर जागरूकता सत्र आयोजित

बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) और CPR का के बारे में दी जानकारी

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल द्वारा राष्ट्रव्यापी पहल 'स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान' के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। यह अभियान निवारक स्वास्थ्य सेवा, जागरूकता कार्यक्रमों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, जिससे मजबूत परिवारों और स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सके।

'स्वस्थ नारी, स्वस्थ परिवार' अभियान के अंतर्गत साबरमती मंडल रेलवे अस्पताल में एक स्वास्थ्य जागरूकता वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता का संचालन वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सुशांत रंजन द्वारा किया गया। उन्होंने महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, शिशुओं एवं बच्चों के लिए

संतुलित आहार और पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर विस्तृत एवं सहज जानकारी साझा की। डॉ. रंजन ने गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए उपयुक्त आहार, आवश्यक औषधीय पूरक आहार, केवल स्तनपान के लाभ, स्तनपान छुड़ाने का उचित समय, एवं पूरक आहार की भूमिका पर विशेष जोर दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्वस्थ खान-पान की आदतों का विकास, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों में, न केवल व्यक्तिगत बल्कि पूरे परिवार एवं समुदाय के स्वास्थ्य सुधार में सहायक सिद्ध होता है। इस अवसर पर प्रस्तुत पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को उपस्थित जनसमूह ने सराहा। जानकारीपूर्ण, सटीक एवं दृश्य सामग्री से युक्त यह सत्र अत्यंत प्रभावशाली रहा। यह पहल पोषण माह एवं स्वस्थ नारी, स्वस्थ परिवार अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य समाज में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करना है।

साथ ही डिवीजन रेलवे अस्पताल के ओपीडी में बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) का प्रदर्शन किया गया। इस सत्र के दौरान सभी प्रतिभागियों को बेसिक लाइफ सपोर्ट, वयस्क कार्डियोपल्मोनरी सेरेब्रल रिससिटेशन (CPCR), ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर (AED) की कार्यप्रणाली और एक अचेत/बेहोश व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों में क्या करना चाहिए झ इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उढफ की व्यावहारिक प्रस्तुति मानव आकृति (मैनिकिन) पर की गई, जिसमें जानकारीपूर्ण और सहभागी सत्र में 75 से अधिक लाभार्थियों को संबोधित किया गया।

एच-1बी वीजा पर आए इंडियन प्रोफेशनल्स को क्यों घबराने की जरूरत नहीं है? अमेरिकी अधिकारी ने दिया ये बड़ा अपडेट

(जीएनएस)। एच-1बी वीजा धारकों में 70% से अधिक भारतीय होते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा इस वीजा की फीस बढ़ए जाने के बाद आईटी प्रोफेशनल्स सदमे में आ गए थे। अमेरिकी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की H-1B वीजा पर चौंकाने वाली घोषणा के बाद टेक कंपनियों के बीच अफरातफरी मच गई थी और कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को अमेरिका तुरंत वापस लौटने का आदेश दे दिया था लेकिनअब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं हैं और ना ही तुरंत वापस लौटने की जरूरत है।

एक अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट किया, "H1B वीजा पर भारतीयों को

रविवार तक लौटने की जरूरत नहीं है और ना ही अमेरिका से प्रवेश करने के लिए 1 लाख डॉलर का भुगतान करने की आवश्यकता है।" यह स्पष्टीकरण ट्रम्प प्रशासन द्वारा प्रत्येक H-1B वीजा कर्मचारी पर अमेरिकी कंपनियों के लिए $100,000 वार्षिक शुल्क लगाने के बाद आया है।

यह कदम भारतीयों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि इन वीजा धारकों में 70% भारतीय होते हैं। अमेरिकी अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि ल-1इ वीजा पर नया शुल्क "केवल नए वीजा अप्लीकेशन पर लागू होगा, नवीनीकरण पर नहीं"।

अधिकारी की यह टिप्पणी उन कई टेक कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो पहले माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॅन, मेटा और जेपी मॉर्गन जैसी कई टेक फर्मों से मिले नोटिस से चिंतित थे। इन कंपनियों ने कर्मचारियों से अमेरिका में ही रहने का आग्रह किया था, और देश से बाहर के लोगों से 21 सितंबर को 12:01 बजे एउ्ळ से पहले लौटने को कहा था।

बिजली विभाग : इंजीनियर की बेहिसाब संपत्ति का सबूतों के साथ पदार्फाश!

अपने पद का इस्तेमाल निजी संपत्ति संचय में करना, राष्ट्र के साथ विश्वासघात से कम नहीं है।

सी॰ एम॰ जैन` भारत में भ्रष्टाचार की कहानियों की कभी कमी नहीं रही, लेकिन कुछ मामले अपनी निडरता, व्यापकता और बेशर्मी के कारण बाकियों से कहीं आगे निकल जाते हैं। डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत समीर किशोरकुमार पांड्या की कहानी ऐसा ही एक मामला है। संदिग्ध भूमि सौदों और अस्पष्ट जीवनशैली विकल्पों की अफवाहों से शुरू हुआ यह मामला समय के साथ आय से अधिक संपत्ति, बेनामी लेनदेन, मिलीभगत से धोखाधड़ी और सरकारी पद के दुरुपयोग की ओर इशारा करने वाले सबूतों के एक अकाट्य ढेर में बदल गया है। यह सिर्फ. एक सरकारी कर्मचारी की कहानी नहीं है; यह उस व्यवस्था का आईना है जो अक्सर सार्वजनिक ज़िम्मेदारी वाले व्यक्तियों को चुपचाप अपनी आधिकारिक शक्ति को निजी साम्राज्यों में बदलने की अनुमति देती है।

1997 को विद्युत विभाग में हुई थी नियुक्ति।

ज्ञात हो कि समीर किशोरकुमार पंड्या 13 नवंबर 1997 को दमन और दीव विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियंता के रूप में सरकारी सेवा में शामिल हुए। 8 मई 1972 को जन्मे, उनके करियर का पथ ऊपर से देखने पर एक सामान्य पथ पर ही चला: वरिष्ठता के माध्यम से पदोन्नति, जिसकी परिणति सहायक अभियंता के रूप में उनके वर्तमान पद पर हुई। कागजी तौर पर, उनका वेतन और वैध आय उन्हें एक मध्यमवर्गीय अधिकारी के दायरे में रखती है। फिर भी, जब कोई उनकी संपत्ति प्रोफाइल की जाँच करता है, तो एक चौंकाने वाला अंतर दिखाई देता है: संपत्ति, जमीन, कॉर्पोरेट साझेदारियाँ और वित्तीय लेन-देन करोड़ों में हैं, जो किसी भी कानूनी आय स्रोत से उचित नहीं ठहराए जा सकते।

परिवार के नाम पर कई बड़ी ओधोगिक इकाइयां।

समीर पंड्या के निकटतम परिवार में उनकी पत्नी सुमिता समीर पंड्या, पुत्र वरुण और पुत्री इशानी शामिल हैं। साक्ष्य दशार्ते हैं कि सुमिता पंड्या संपत्ति और संपदा संचय में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं, और उनका नाम कंपनी साझेदारी और भूमि स्वामित्व अभिलेखों में बार-बार दिखाई देता है। 1. आर.के. पेट प्रोफाइल्स, जो भीमपुर, दमण में स्थित है, जहाँ सुमिता पंड्या, केतन पंड्या के साथ साझेदार हैं। 2. मैक्स एक्सट्रूजन्स प्राइवेट लिमिटेड, सोमनाथ दमन, जहाँ वह दीपक प्रभुदास मिस्त्री के साथ साझेदार हैं। दोनों कंपनियाँ उच्च पूँजी कारोबार वाले क्षेत्रों में काम करती हैं।

35 करोड़ से अधिक कि संपत्ति का मालिक।

प्राप्त जानकारी और सत्यापित अभिलेखों के अनुसार, 2015 और 2020 के बीच, पांड्या परिवार ने कुल 7,793.64 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 22 भूखंड अर्जित किए। इसके अतिरिक्त यदि बाकी तथा कुल संपत्ति का हिसाब लगाए तो 23657 वर्ग मीटर जमीन का पता चलता है जिसमे मकाम, प्लॉट, कंपनियाँ आदि शामिल है, वही यदि उक्त कुल संपत्ति का आज के समय में बाजार भाव से हिसाब किया जाए तो उक्त संपत्ति आज के हिसाब से 35 करोड़ से अधिक कि है। जो एक सहायक अभियंता की कमाई क्षमता से कहीं अधिक है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आँकड़ों में संयंत्र और मशीनरी, स्टॉक, बैंक बैलेंस, सावधि जमा, डीमैट खाते, सोना, चाँदी या अन्य चल संपत्तियाँ शामिल नहीं हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती।

सूत्रों की माने तो इसके अतिरिक्त भी कई अन्य फ्लैट, बंगले, कृषि भूमि और संपत्तियां भी हो सकती हैं। केवल इतना ही नहीं, कई संपत्तियाँ परिवार के सदस्यों, व्यावसायिक साझेदारों और संभवतः दूर के रिश्तेदारों के नाम पर भी पूर्व में हस्तांतरित भी की गई हो सकती हैं। ऐसा इस लिए क्यों की समीर पांड्या और उनकी पत्नी दोनों दमन और दीव के मूल निवासी नहीं हैं, इसलिए इस बात का संदेह प्रबल है कि उनके मूल क्षेत्रों में माता-पिता, भाई-बहनों या सहयोगियों के नाम पर महत्वपूर्ण संपत्तियाँ हो सकती हैं। और वैसे भी आम तौर पर देखा जाता है की जब भी किसी भ्रष्ट सरकारी अधिकारी के यहाँ छापेमारी होती है तो जमीन से सोना चाँदी निकलता है, नोट गिनने के लिए सरकारी जांच एजेंसियों को नोट गिनने की मशिने मंगवानी पड़ती है और बेनामी संपातियों के कागजात देखकर तो जांच करने वाले अधिकारी खुद भौचक्के रह जाते है। इस मामले में भी जांच एजेंसियों को ऐसा ही कुछ देखने को मिले मिल सकता है। बच छापा पड़ने कि देर है!

स्पष्ट आंकड़े सामने लाने के लिए छापेमारी आवश्यक।

उक्त अभियंता, अभियंता के परिवार के सदस्यों और अन्य सहियोगियों ने मिलकर जनता और सरकार को कुल कितना चुना लगाया इसके स्पष्ट आंकड़े सामने लाने के लिए भी छापेमारी आवश्यक है। छापेमारी के बाद ही यह भी पता चल पाएगा कि एक कनिष्ठ अभियंता अपने वेतन से अपने परिवार के भरण-पोषण, बच्चो कि पढ़ाई लिखाई जैसे आम खर्चो के बाद भी अपने परिवार को करोड़ों कि संपत्ति का मालिक बनाने में कैसे कामियाब हुआ! आम जनता अपनी सालो कि मेहनत और बचत के बाद एक प्लॉट नहीं ले सकती वही उक्त परिवार ने थोड़े ही समय में दर्जनों प्लॉट कैसे हंसिल किए यह एक यक्ष प्रश्न है। आँकड़ों से परे, जनता के विश्वास का सिद्धांत निहित है। भ्रष्टाचार के जरिए गबन किया गया हर एक रुपया जनता से चोरी है: वे करदाता जो सरकारी वेतन देते हैं, वे नागरिक जो विश्वसनीय बिजली और बुनियादी ढाँचे पर निर्भर हैं। बिजली विभाग के एक अधिकारी, जिसका काम महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की देखरेख करना है, के लिए अपने पद का इस्तेमाल निजी संपत्ति संचय में करना, राष्ट्र के साथ विश्वासघात से कम नहीं है।

भावनगर मंडल के वेरावल पोस्ट के रेलवे सुरक्षा बल ने यात्री को ₹2.69 लाख कीमत का सामान लौटाया

पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के कर्मचारी सदैव यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को प्राथमिकता देते हुए हर संभव मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) वेरावल पोस्ट के जवानों ने ईमानदारी और सजगता का परिचय देते हुए एक यात्री का कीमती पिट्ठू बैग सही-सलामत वापस सौंपा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹2,69,000/- थी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 17 सितम्बर, 2025 (बुधवार) को एएसआई श्री विकास यादव अपने स्टाफ के साथ गश्त के दौरान वेरावल स्टेशन के बुकिंग ऑफिस के सामने एक काला लावारिस पिट्ठू बैग पाया। आस-पास यात्रियों से पूछताछ करने पर कोई जानकारी प्राप्त न होने पर पंचों की उपस्थिति में बैग की जाँच की गई, जिसमें एक मोबाइल नंबर मिला।

उस नंबर पर संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि यह बैग यात्री श्री कमलेश का है, जो ट्रेन संख्या 19119 सवारी गाड़ी से राजकोट से वेरावल यात्रा कर रहे थे और अनजाने में स्टेशन पर बैग छूट गया था। तत्पश्चात आरपीएफ द्वारा यात्री से संपर्क कर जानकारी दी गई और उनके वेरावल पोस्ट पर पहुँचने पर सामान की पहचान कराकर बैग उन्हें सुरक्षित सौंप दिया गया।

बैग में एप्पल कंपनी का आईपैड, डेल कंपनी का लैपटॉप, एप्पल की डिजिटल घड़ी, एयरपॉड्स, रेडमी कंपनी का मोबाइल, एप्पल का पावर बैंक, हार्ड डिस्क, अरमानी का चश्मा, चार्जर एवं दस्तावेज फाइल आदि सामान मौजूद था। यात्री ने इनकी कुल कीमत लगभग ₹2,69,000/- बताई।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अभिजात चंद्रकांत शेठ ने अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 11वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की

सरकार देश भर में समान रूप से डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि डॉक्टर-रोगी अनुपात 1:1000 बनाए रखने की विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के अनुरूप काम किया जा सके: चेयरमैन, एनएमसी

"राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड और एनएमसी द्वारा नई पहल की शुरूआत की जा रही है, जैसे कि पारंपरिक शारीरिक शिक्षा के साथ कौशल-आधारित और आभासी शिक्षा को एकीकृत करना, ताकि योग्यता-आधारित चिकित्सा शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके"

इस अवसर पर 250 स्नातकोत्तर और डीएम छात्रों और 100 एमबीबीएस स्नातकों के पहले बैच को डिग्री प्रदान की गई

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अभिजात चंद्रकांत शेठ ने आज यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान (एबीवीआईएमएस) और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 11 वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) डॉ. सुनीता शर्मा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉ. विनोद कोटवाल भी उपस्थित थे।

अपने संबोधन में डॉ. शेठ ने स्नातक छात्रों के साथ-साथ उनके अभिभावकों और संकाय सदस्यों को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में छात्रों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देने में उनके समर्पण के लिए बधाई दी। उन्होंने देश भर में 1:1000 का एक समान डॉक्टर-रोगी अनुपात बनाए रखने की विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश को पूरा करने के लिए देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। डॉ. शेठ ने

स्नातक (यूजी) से स्नातकोत्तर (पीजी) के बीच 1:1 का संतुलित अनुपात हासिल करने के लिए चल रहे प्रयासों को भी रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की गुणवत्ता को विकसित देशों के मानकों के बराबर लाना है।

डॉ. शेठ ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा शुरू की जा रही नई पहलों पर को भी रेखांकित किया जैसे कि योग्यता-आधारित चिकित्सा शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारंपरिक शारीरिक शिक्षा के साथ-साथ कौशल-आधारित और आभासी शिक्षा को एकीकृत करना। उन्होंने छात्रों को अपने स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने, चुनौतियों का डटकर सामना करने और आजीवन सीखने वाले बने रहने के लिए प्रेरित किया।

डॉ. विनोद कोटवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज का यह अवसर छात्रों की वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम है और कहा, "यह राष्ट्र के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति आपकी आजीवन प्रतिबद्धता की शुरूआत है।" उन्होंने एबीवीआईएमएस को हाल ही में मिली एनएबीएच मान्यता के लिए भी बधाई दी, जो "गुणवत्ता, सुरक्षा और रोगी-केंद्रित देखभाल के प्रति संस्थान की अटूट प्रतिबद्धता की मान्यता है"। डॉ. कोटवाल ने छात्रों से आग्रह किया कि वे ज्ञान, खोज और सेवा को अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में ईमानदारी, करुणा और सम्मान के साथ जारी रखें। उन्होंने कहा, "चिकित्सा केवल बीमारी का इलाज करने के बारे में नहीं है; यह पीड़ित रोगियों की देखभाल करने के बारे में है।"

डॉ. सुनीता शर्मा ने स्नातक छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, "आज आप सिर्फ. डिग्री प्राप्त नहीं कर रहे हैं बल्कि आप एक गहन ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं—रोग निवारण, नेतृत्व और राष्ट्र की सेवा, चाहे आप किसी भी क्षमता में चुनें।" चाहे आप नैदानिक देखभाल, चिकित्सा अनुसंधान या शिक्षा के क्षेत्र में हों, उन्होंने सलाह दी, "अपने काम को सहानुभूति, प्रमाण और उत्कृष्टता से प्रेरित होने दें।"

चिकित्सा पेशे की पवित्रता पर जोर देते हुए, डॉ. शर्मा ने घोषणा की, 'यह एक महान कार्य है जो करुणा और मानव जीवन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर आधारित है।' उन्होंने स्नातकों को विनम्र और जमीन से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करते हुए समापन किया, चाहे वे जीवन में कितनी भी दूर क्यों न पहुँच जाएँ या कितनी भी उपलब्धियाँ हासिल कर लें।

समारोह के दौरान, 250 स्नातकोत्तर और डीएम छात्रों और 100 एमबीबीएस स्नातकों के पहले बैच को उपाधियाँ प्रदान की गईं। इस अवसर पर एबीवीआईएमएस (संहिता) की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की गई।

एबीवीआईएमएस और आरएमएलएच के बारे में

1932 में विलिंगडन नर्सिंग होम के रूप में स्थापित, यह अस्पताल 1,532 बिस्तरों वाला एक प्रमुख संस्थान बन गया है जो विभिन्न विशेषज्ञताओं और अति-विशिष्टताओं में व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। 2019 में इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान (एबीवीआईएमएस) और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएलएच) कर दिया गया। यह अस्पताल प्रतिवर्ष 100 एमबीबीएस सीटों के साथ-साथ 203 स्नातकोत्तर और 48 डीएम/एमसीएच सीटें प्रदान करता है।

यह अस्पताल प्रत्येक वर्ष लगभग 12 लाख बा'रोगियों और 60,000 आंतरिकरोगियों की सेवा करता है और बिना किसी अस्वीकृति नीति के चौबीसों घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करता है। एबीवीआईएमएस और डॉ. आरएमएलएच एक तृतीयक देखभाल केंद्र है जो भारत के लोगों को लगभग सभी विशेषज्ञता और अति-विशिष्टता क्षेत्रों में चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान करता है। डॉ. आरएमएलएच सीजीएचएस लाभार्थियों, माननीय सांसदों, पूर्व सांसदों, मंत्रियों, न्यायाधीशों और अन्य अति-विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों को भी चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करता है।

इस कार्यक्रम में एबीवीआईएमएस के निदेशक डॉ. (प्रो.) अशोक कुमार, एबीवीआईएमएस की डीन डॉ. आरती मारिया, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, संकाय सदस्य और अभिभावक भी उपस्थित थे।

केंद्रीय मत्स्य पालन सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने कोच्चि में आईसीएआर-सीआईएफटी के कामकाज की समीक्षा की

'पोस्ट हार्वेस्ट' मत्स्य प्रबंधन के लिए मत्स्य प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करने हेतु रोडमैप की मांग

(जीएनएस)।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में केंद्रीय सचिव, मत्स्य पालन विभाग, डॉ. अभिलक्ष लिखी ने 19 सितंबर 2025 को आईसीएआर - केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी) के कामकाज की समीक्षा करने के लिए कोच्चि, केरल का दौरा किया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), मत्स्य पालन स्टार्टअप्स, समुद्री खाद्य निर्यातकों और अन्य मत्स्य पालन हितधारकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

डॉ. अभिलक्ष लिखी ने आधुनिक तकनीकों को अपनाकर मत्स्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में कमियों को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आईसीएआर-सीआईएफटी और अन्य हितधारकों से मछली की पैदावार और उन्हें पकड़ने (पोस्ट हार्वेस्ट) के बाद उनके बेहतर प्रबंधन को सुदृढ़ करने और मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया।

मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मत्स्य पालन) श्री

सागर मेहरा ने "पोस्ट हार्वेस्ट" प्रबंधन एवं मूल्य संवर्धन हेतु मत्स्य प्रौद्योगिकी" पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने मत्स्य उत्पादों में विविधता लाने और बाजार के अवसरों को खोलने तथा क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक मूल्य संवर्धन तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि आईसीएआर संस्थानों के सशक्त अनुसंधान एवं विकास द्वारा समर्थित 'पोस्ट हार्वेस्ट' प्रबंधन, नुकसान को कम कर सकता है और मछुआरों की आय बढ़ा सकता है। इससे एक लचीली और प्रतिस्पर्धी मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला का निर्माण हो सकता है।

डॉ. लिखी ने आज 20 सितंबर 2025 को थोप्पुमपडी स्थित कोच्चि फिशिंग हार्बर का दौरा किया और अब तक हुए विकास और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मछुआरों से बातचीत की और उन्हें टूना, झींगा, स्क्विड आदि सहित प्रमुख मछली पकड़ने वाली प्रजातियों के बारे में बताया। उन्होंने जहाज पर मौजूद मछुआरों और पोत संचालकों से भी बातचीत की और उनकी चुनौतियों और ट्रांसपोंडरों की कार्यप्रणाली को समझा। केंद्रीय सचिव ने बंदरगाह प्राधिकरण के अधिकारियों से पीएमएमएसवाई के तहत स्वीकृत चल रही फिशिंग हार्बर परियोजना को समय पर पूरा करने का आग्रह किया।

कोच्चि बंदरगाह के बारे में

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग ने मार्च 2022 में केरल के थोप्पुमपडी में कोचीन फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जिसकी कुल लागत 169.17 करोड़ रुपये है। इसके लिए सागरमाला के तहत बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के साथ समन्वय में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत 100 करोड़ रुपये तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

एसएससी के फीडबैक पोर्टल को मिली अच्छी प्रतिक्रिया; परीक्षा में व्यवधान के वास्तविक मामलों के लिए पुनः परीक्षाएं निर्धारित की जाएंगी

नई दिल्ली, 20 सितंबर - कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने कहा है कि उसके नए शुरू किए गए फीडबैक पोर्टल को संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। इस पोर्टल के शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर करीब 10,000 उम्मीदवारों ने अपने परीक्षा अनुभव साझा किए हैं।

एसएससी अधिकारियों ने बताया कि लगभग 2,000 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा के दौरान कथित तकनीकी व्यवधानों की सूचना दी है। आयोग अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रत्येक मामले का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रहा है। एक अधिकारी ने कहा, "जहाँ व्यवधान वास्तविक पाए जाते हैं,

प्रभावित उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। पुनर्परीक्षाएँ 26 सितंबर, 2025 को या उससे पहले निर्धारित की जाएँगी।"

आयोग ने कहा कि वह परीक्षाओं के संचालन में निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक देश भर में 7.16 लाख उम्मीदवार सफलतापूर्वक परीक्षा दे चुके हैं। अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की कि 19 सितंबर को किसी भी पाली को रद्द या पुनर्निर्धारित नहीं किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरे दिन सुचारू रूप से चली।

सीजीएलई भारत की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक है, जिसमें केंद्र सरकार की नौकरियों के इच्छुक लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। फीडबैक पोर्टल की शुरूआत को इस प्रक्रिया को और अधिक संवेदनशील और अभ्यर्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि परीक्षा प्रणाली की समग्रता को बनाए रखते हुए समस्याओं का वास्तविक समय में समाधान किया जाए।

खेल विभाग स्वच्छता बढ़ाने और लंबित मामलों के समाधान के लिए विशेष अभियान 5.0 में हिस्सा लेगा

(जीएनएस)।

भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का खेल विभाग, उत्तरदायी सुशासन को बढ़ावा देने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विशेष अभियान 4.0 की उल्लेखनीय उपलब्धियों के बाद, विभाग ने विशेष अभियान 5.0 के शुरूआती चरण के लिए आधारभूत कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप, इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उत्तरदायी प्रबंधन और वैज्ञानिक निपटारें को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

खेल विभाग ने 2 अक्टूबर, 2024 को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन 5.0 के उत्साहपूर्ण शुभारंभ के साथ विशेष अभियान 4.0 की शुरूआत की, जिसमें फिटनेस और स्वच्छता के विषयों को राष्ट्रीय गौरव के एक सशक्त प्रतीक के रूप में दर्शाया गया।

विभाग ने अपने अधीनस्थ संगठनों - जिनमें भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई), राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय (एनएसयू), राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (एनएडीए), और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) शामिल हैं, के साथ मिलकर सांसदों के 15 लंबित मामलों का निपटारा किया। इसमें 30 जन शिकायतों का समाधान करते हुए दो संसदीय आश्वासनों को पूरा किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक चरण पर प्रगति की सक्रिय निगरानी कर रहे थे।

जमीनी स्तर पर, इस विभाग के अंतर्गत आने वाले संगठनों के क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों में फैले 44 चिन्हित स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाए गए। इस समन्वित प्रयास के परिणामस्वरूप 12,000 वर्ग फुट जगह का पुनर्ग्रहण हुआ और कई नए उपलब्ध क्षेत्रों को मूल्यवान उपयोगिता स्थलों में परिवर्तित किया गया। इसके अलावा, अभियान के दौरान कबाड़ के निपटान से 1,76,000 रुपये की आय प्राप्त हुई, जो स्वच्छता के प्रति सततता और संसाधनशीलता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभाग और इसके अंतर्गत आने वाले संगठनों द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 24 ट्वीट भी साझा किए गए, जिनमें अभियान की पहुँच और दृश्यता बढ़ाने के लिए #SpecialCampaign4.0 और #SwachhBharat हैशटैग का उपयोग किया गया।

खेल विभाग विशेष अभियान 5.0 को अत्यंत प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर स्वच्छता के उच्चतर मानक स्थापित करना तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस) पर डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन, 2024

डिजिटल युग में समय के उपयोग, देखभाल कार्य और लैंगिक भूमिकाओं के बदलते पैटर्न की खोज

(जीएनएस)।

भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), विकास अध्ययन केंद्र (सीडीएस), तिरुवनंतपुरम के सहयोग से, 22 सितंबर, 2025 को तिरुवनंतपुरम, केरल में समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस), 2024 पर एक डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य डेटा उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है, जिससे सामाजिक-आर्थिक नीति निर्माण में टीयूएस डेटा के महत्व और अनुप्रयोगों के बारे में अहम जानकारी प्राप्त हो सके।

समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस) इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है कि व्यक्ति विभिन्न भुगतान और अवैतनिक गतिविधियों, देखभाल कार्य, सीखने और अवकाश के दौरान अपने समय का किस प्रकार उपयोग करते हैं। टीयूएस 2024, 2019 के पिछले सर्वेक्षण पर आधारित है और भारत में कार्य और जीवन पद्धति में बदलावों, विशेष रूप से लैंगिक भूमिकाओं और विकसित होती सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के संदर्भ में तुलनात्मक साक्ष्य प्रदान करता है।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि श्री के.एम. चंद्रशेखर, पूर्व कैबिनेट सचिव, डॉ. सौरभ गर्ग, आईएएस, सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, डॉ. इंदिरा हिरवे, पूर्व निदेशक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, प्रो. वीरमणि, निदेशक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज (सीडीएस) और सुश्री गीता सिंह राठौर, महानिदेशक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) उपस्थित रहेंगे।

इस कार्यक्रम में लगभग 175 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिनमें शोधकर्ता, अर्थशास्त्री, नीति-निमार्ता, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, शिक्षा जगत और मीडिया के प्रतिष्ठित संस्थान शामिल होंगे। कार्यक्रम में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद सर्वेक्षण की रूपरेखा, प्रमुख निष्कर्षों और टीयूएस डेटा की उपयोगिता पर तकनीकी सत्र, एक पैनल चर्चा और प्रतिभागियों के साथ एक मुक्त संवादात्मक सत्र होगा। यह कार्यक्रम टीयूएस डेटा की उपयोगिता और लिंग, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा अर्थव्यवस्था पर समावेशी नीतियों को आकार देने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा।

तकनीकी सत्र समय उपयोग सर्वेक्षण 2024 के डिजाइन, कार्यप्रणाली और प्रमुख निष्कर्षों के साथ-साथ सर्वेक्षण के पहले दौर की तुलनात्मक अंतर्दृष्टि पर केंद्रित होगा।

कौन हैं संजय यादव? जिसकी वजह से लालू परिवार में हो रहे खुलेआम झगड़े, तेज प्रताप के बाद, रोहिणी-मीसा भी गुस्सा

(जीएनएस)।

बिहार की राजनीति में लालू यादव का परिवार हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। घर के अंदरूनी झगड़े अब खुले मंच पर आने लगे हैं। तेज प्रताप यादव के बाद बहन रोहिणी आचार्य और मिसा भारती भी बगावत के मूड में हैं। दिलचस्प ये है कि इस पूरे झगड़े के पीछे जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, वो लालू परिवार का सदस्य नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव का खासमखास-राज्यसभा सांसद संजय यादव हैं।

कहा जा रहा है कि संजय यादव न सिर्फ तेजस्वी की पॉलिटिक्स को दिशा दे रहे हैं, बल्कि धीरे-धीरे परिवार में दरार डालने वाले किरदार की तरह सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट लिखकर अपना गुस्सा जाहिर किया और साफ कहा कि उन्हें न तो पद की लालसा है और न राजनीति की भूख-उनके लिए सिर्फ आत्मसम्मान ही सबसे ऊपर है। वहीं मीसा भारती ने भी पार्टी के अंदर इसको लेकर विरोध किया है।

अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये संजय यादव कौन हैं, जो लालू परिवार की एकजुटता को हिला रहे हैं और आरजेडी में हलचल मचा रहे हैं? ऐसे में आइए संजय याजव की पूरी कुंडली जानते हैं, साथ में ये भी जानेंगे कि तेजस्वी यादव के साथ इनकी दोस्ती इतनी गहरी कैसे हुई।

कौन हैं संजय यादव

- हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल सिरोही गांव के रहने वाले संजय यादव वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ सांसद तक सीमित नहीं है। फखऊपार्टी के भीतर फैसलों और रणनीतियों में उनका बड़ा दखल माना जाता है। संजय का ज्यादातर समय डेटा एनालिसिस और बिहार की राजनीतिक-सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करने में जाता है।
- संजय यादव का जन्म 24 फरवरी 1984 को हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले के नांगल सिरोही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रभाती लाल और माता का नाम बसंती देवी है। संजय यादव ने 20 जून 2014 को सुनीष्ता से शादी की है और उनके एक बेटा और दो बेटियां हैं - मिराया और तान्या राव।

- संजय यादव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद, मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री ली है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में तीन मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम किया। लेकिन 2010 के बाद उन्होंने राजनीति में सक्रियता बढ़ाई।
- 2024 में संजय यादव को आरजेडी ने राज्यसभा के लिए नामित किया। इससे पहले, उन्होंने पार्टी के लिए कई चुनावी रणनीतियों में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, उन्होंने राजनीति में आने से पहले संकोच किया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव और अन्य नेताओं के दबाव में उन्होंने यह जिम्मेदारी स्वीकार की।
- संजय यादव राजनीतिक सफर और पार्टी में प्रभाव

संजय यादव ने 2012 में आरजेडी जॉइन की। 2015 और 2020 के बिहार चुनावों में उन्होंने पार्टी को मजबूती देने में सक्रिय भूमिका निभाई। तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी के तौर पर उनकी छवि पार्टी में मजबूत है।

हालांकि विवाद भी संजय के राजनीतिक करियर का हिस्सा रहे। 2021 में तेज प्रताप यादव ने उन्हें ठफक्क कहकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके अलावा संजय यादव को बिहार जमीन घोटाले से जुड़े मामले में इडक ने पूछताछ के लिए बुलाया। 2024 में संजय यादव को आरजेडी ने राज्यसभा के लिए नामित किया और वे राज्यसभा सांसद बने।

आरजेडी के भीतर संजय यादव पर लगातार हस्तक्षेप के आरोप लगते रहे हैं। पार्टी कार्यकताओं का तो यहां तक कहना है कि झंडे और प्रचार सामग्री भी उनकी ही कंपनी से खरीदनी पड़ती है। 2021 में जब जगदानंद सिंह के खिलाफ आकाश यादव को सस्पेंड किया गया था, तब भी पर्दे के पीछे संजय यादव की भूमिका बताई गई थी। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी निशाना साधा और इसे "सामाजिक न्याय का पाखंड" करार दिया।

- तेजस्वी यादव और संजय यादव की दोस्तीः क्रिकेट से राजनीति तक

संजय और तेजस्वी की दोस्ती क्रिकेट के मैदान से शुरू हुई। तेजस्वी के आईपीएल दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के समय संजय उनसे जुड़े। जब लालू यादव जेल गए, तो परिवार ने तेजस्वी को पटना में सक्रिय राजनीति में लाने की जिम्मेदारी दी। उसी समय संजय यादव को बुलाया गया और तभी से उनकी भूमिका लगातार बढ़ती गई।

संजय यादव की एंट्री 2012 में तब हुई जब लालू जेल में थे और तेजस्वी क्रिकेट छोड़ राजनीति में उतर रहे थे। दिल्ली से पटना लौटते तेजस्वी को एक भरोसेमंद साथी चाहिए था, तभी अखिलेश यादव ने उनकी मुलाकात संजय से कराई। संजय पहले सपा में रणनीति बना चुके थे, लेकिन सब छोड़ पटना आ गए। देखते ही देखते वे तेजस्वी के "आंख-कान" बन गए। खास बात ये कि लालू के जेल से बाहर आने पर भी उनका प्रभाव घटा नहीं, बल्कि और बढ़ा। आज हाल ये है कि आरजेडी में अगर किसी को लालू या तेजस्वी तक पहुंचना है, तो दरवाजा पहले संजय से ही खुलता है।

राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि आज तेजस्वी यादव को "युवा और आधुनिक नेता" के रूप में पेश करने में संजय यादव की रणनीतिक भूमिका अहम रही है। संजय यादव की पहचान तेजस्वी यादव के करीबी सलाहकार के रूप में बन चुकी है। उनकी रणनीतियों ने पार्टी को 2015 और 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में सफलता दिलाई।

संजय यादव संपत्ति

संजय यादव के पास कुल 2 करोड़ रुपये की संपत्ति है। संजय यादव के पास एक लाख कैस और 44 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों में जमा है। एनएसएस, डाक बचत में 7 लाख रुपये और एलआईसी और अन्य बीमा में 9 लाख रुपये निवेश है। बतौर राज्यसभा सांसदों को संजय यादव को लगभग हर महीने 2 लाख रुपये सैलरी मिलती है।

- परिवार और पार्टी में बढ़ती खींचतान

संजय यादव की बढ़ती भूमिका और तेजस्वी के लिए रणनीतिक फैसलों में उनकी भागीदारी ने परिवार के भीतर नाराजगी पैदा की है। तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य ने भी अपनी पोस्ट के जरिए अपने असंतोष का इशारा किया है।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह खींचतान भविष्य में आरजेडी के भीतर और लालू परिवार में पद, प्रभाव और सत्ता को लेकर और बढ़ सकती है। हाल ही में, 'बिहार अधिकार यात्रा' के दौरान एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें संजय यादव तेजस्वी यादव की फ्रंट सीट पर बैठे थे। इस पर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई और इसे पार्टी के भीतर चल रहे आंतरिक संघर्ष का संकेत माना।

संजय यादव सिर्फ एक सांसद